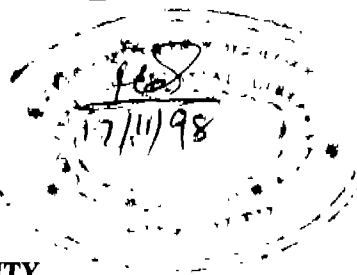




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 124]
No. 124]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 1998/ज्येष्ठ 18, 1920
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 1998/JYAISTHA 18, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 15 (आर ई -98)/1997-2002

नई दिल्ली, 8 जून, 1998

फा. संख्या पी आर यू/ए एस/97098/ पी एन क्लैरीफिकेशन का. आ. संख्या 283 (अ).—तारीख 31 मार्च 1997 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (2) में यथा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैरा 4.11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1), 1997-2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

1. निम्नलिखित को पैरा 4.31 के रूप में जोड़ा जाएगा :

“ऐसे मामले जहाँ आवेदनों पर आर ए एल सी/जेड ए एल सी/ए एल सी/क्षेत्रीय ई पी सी जी समिति/जोनल ई पी सी बी स्कीम/मुख्यालय ई पी सी जी समिति/विशेष लाइसेंसिंग समिति/निर्यात लाइसेंसिंग समिति/उच्च अधिकार प्राप्त लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार किया जाना है, वहाँ निर्धारित फीस सहित आवेदन पत्र की मूल प्रति संबंधित प्रादेशिक लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास फाईल की जाएगी और उसकी एक सत्यापित प्रति उपर्युक्त समितियों के पास फाईल की जाएगी।”

2. पैरा 6.14 के अंतिम वाक्य में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :

“ऐसे मामले जहाँ लाइसेंस द्वारा कवर लागत बीमा भाड़ा मूल्य वास्तविक रूप से उपयोग किए गए लागत बीमा भाड़ा मूल्य से अधिक है, वहाँ लाइसेंसधारक बाद में आयातों के अधिक लागत बीमा भाड़ा मूल्य को कवर करने के लिए अतिरिक्त फीस देगा।”

3. पैरा 6.14 के अन्त में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

“यदि ई पी सी जी लाइसेंस का वास्तविक उपयोग, शून्य शुल्क ई पी सी जी स्कीम की प्रारम्भिक सीमा के 90 प्रतिशत से कम है तो लाइसेंसधारक को सीमा शुल्क प्राधिकारियों को तत्काल 24 प्रतिशत ब्याज के साथ पूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान की अपेक्षा होगी और एक माह की अवधि के भीतर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस आश्च का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।”

4. पैरा 6.11 (ग) और पैरा 6.19 में जहाँ कहीं “24 प्रतिशत ब्याज” शब्द आया है उसे “प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत ब्याज” शब्द और अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. पैराग्राफ 7.9 (1) के प्रथम वाक्य को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

“क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति/जोनल क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को प्रथम लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, आवेदक अनुलग्नक के रूप में परिशिष्ट 11 ख सहित परिशिष्ट 11 क में दिए गए आवेदन की एक प्रति विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को भेजगा।”

6. पैराग्राफ 7.4 (क) के अधीन उप पैराग्राफ को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

“स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और इसकी बनी वस्तुओं के निर्यात के मामले में आवेदन परिशिष्ट 27 में दिए गए संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और मात्रा, अपशिष्ट तथा मूल्य संवर्धन मानदण्ड नीति के अध्याय 8 और प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 8 के अनुसार होंगे।”

7. पैराग्राफ 7.28 ख को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

“निर्यात और आयात नीति 1992—97 के अनुसार जारी किए गए मात्रा आधारित/मूल्य आधारित लाइसेंस नियमितीकरण के प्रयोजन के लिए नीति/प्रक्रिया, 1992—97 (आर ई-96) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे। तथापि, ऐसे मामलों में भी लाइसेंसधारक को निर्यात और प्राप्ति बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें निर्यात आय की प्राप्ति को दर्शाया गया हो।”

8. पैराग्राफ 7.38 के अधीन उप पैराग्राफ के प्रथम वाक्य को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

“जिन मामलों में प्राप्ति नहीं की गई है वहां प्रारम्भ में डी ई पी बी को गैर हस्तांतरणीय पृष्ठांकन सहित जारी किया जाएगा ताकि निर्यातक अपने प्रयोग के लिए आयात कर सके। फिर भी, प्राप्ति मिलने पर, डी ई पी बी पर हस्तांतरणीयता को पृष्ठांकित किया जाएगा। जिन मामलों में आवेदक प्राप्ति के पश्चात् डी ई पी बी के लिए आवेदन करता है, वहां डी ई पी बी को हस्तांतरणीयता पृष्ठांकन सहित जारी किया जाएगा।”

9. पैराग्राफ 15.4 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“आई ई सी कोड जारी करने वाला लाइसेंसिंग प्राधिकारी पर्याप्त कारणों को लिखित रूप से रिकार्ड करके 5000/- रु. के जुर्माने के भुगतान पर हुई देरी को माफ कर सकता है।”

10. पैराग्राफ 15.4 के शीर्षक में आए “स्वामित्व” शब्द को हटा दिया जाएगा।

11. परिशिष्ट 32 ख के अधीन निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“टी यू वी बायरन (इंडिया), 312, नीलकंठ कमर्शियल सैन्टर, सहार रोड, सहार, मुंबई-400099।”

12. परिशिष्ट 32 ख के शीर्षक को संशोधित करके “आई एस/आई एस ओ 9000 (श्रृंखला) प्रमाणीकरण अभिकरणों की सूची” पढ़ा जाएगा।

13. डब्ल्यू एच ओ जी एम पी प्रमाणीकरण अभिकरणों की सूची।

(क) संबंधित राणों के औषध नियंत्रक/एफ डी ए आयुक्त।

14. जैसा कि परिशिष्ट 28 क में दिया गया है क्रम संख्या 65 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के प्रति डी ई पी बी हकदारी के परिकलन के लिए मूल्य क्षमता से संबंधित कॉलम 4 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— “750/- रु. प्रति ग्रा”

15. निम्नलिखित को पैराग्राफ 6.8 क के तौर पर जोड़ा जाएगा :—

“इलेक्ट्रॉनिक्स और साफ्टवेयर से संबंधित आवेदनों पर, निर्यात के साथ पूंजीगत वस्तुओं के अन्तः संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नोडल/नामित अधिकारी से प्राप्ति सिफारिश के आधार पर नीचे दी गई विधीय शक्ति के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा :—

लागत बीमा भाड़ा मूल्य	सक्षम प्राधिकारी
2 करोड़ रुपए तक	क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण का प्रमुख
2 करोड़ रु. से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	जोनल संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार
10 करोड़ रु. से अधिक लेकिन 20 करोड़ रुपए तक	महानिदेशक, विदेश व्यापार
20 करोड़ रुपए से अधिक	वाणिज्य सचिव

आवेदन की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के संबंधित नोडल/नामित अधिकारी के पास भेजी जाएगी और सिफारिश प्राप्ति होने के बाद उसे ई पी सी जी समिति के समक्ष पेश किए बिना लाइसेंस जारी किए जाएंगे।”

16. संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के सामने क्रमांक (5) के बाद कालम 4 में भिन्नलिखित को कालम 2 में क्रमांक-2 के अनुसार जोड़ा जाएगा।

(6) सहारनपुर

इसके परिणामस्वरूप, क्रमांक-10 के सामने कालम-4 में उल्लिखित जिला सहारनपुर हटा दिया गया है और मुजफ्फरनगर की संख्या बदलकर क्रमांक (1) हो गई है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 15 (RE-98)/1997-2002

New Delhi, the 8th June, 1998

F. No. PRU/AS/97098/PN Clarification.—In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997-2002, as notified in the Gazette of India extraordinary, Part-II—Section 3—Sub-section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-97, the Director General of Foreign Trade hereby makes following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1), 1997-2002 :

(1) The following shall be added as paragraph 4.31 :

“In cases where application is to be considered by RALC/ZALC/ALC/Regional EPCG Committee/Zonal EPCG scheme/Hqrs. EPCG Committee/Special Licensing Committee/Export licensing Committee/High Powered Licensing Committee, the original copy of the application alongwith prescribed fee shall be filed with regional licensing authorities concerned and an attested copy of the same shall be filed with the above Committees”.

(2) The last sentence of paragraph 6.14 shall be amended to read as under :

“In cases, where CIF value actually utilised is more than the CIF value covered by the licence, the licence holder shall furnish additional fee to cover the excess CIF value of imports subsequently”.

(3) The following shall be added at the end of paragraph 6.14 :

“If the actual utilisation of the EPCG licence is below 90% of the threshold limit of the zero duty EPCG scheme, the licence holder shall be required to pay full customs duty together with 24% interest immediately to the Customs authorities and produce evidence to that effect to the concerned licensing authority within a period of one month”.

(4) The word ‘24% interest’ wherever appearing in paragraph 6.11 (c) and paragraph 6.19 shall be replaced by the word and expression ‘24% interest per annum’.

(5) The first sentence of paragraph 7.9 (i) shall be amended to read as under :

“While applying for the first licence to RALC/ZALC, the applicant shall endorse a copy of the application as given in Appendix 11A together with Appendix 11B as annexure to the Special Advance Licensing Committee”.

(6) The sub paragraph under paragraph 7.4 (a) shall be amended to read as under :

“In case of export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the application shall be made to the licensing authority concerned as given in Appendix 27 and the quantity, wastage and value addition norms shall be as given in Chapter 8 of the Policy and Chapter 8 of the Handbook of Procedures”.

(7) Paragraph 7.28B may be amended to read as under :

“Quantity based/Value based licences issued as per Export and Import Policy 1992-97, shall be governed, for the purpose of regularisation, in accordance by the provisions of that Policy/Procedures, 1992-97 (RE-96). However, in such cases also, the licence holder shall be required to furnish Bank Certificate of Export and Realisation showing realisation of export proceeds.”

(8) The first sentence of sub paragraph under paragraph 7.38 shall be amended to read as under :

“The DEPB shall be initially issued with non transferable endorsement in cases where realisation has not taken place to enable the exporter to effect imports for his own use. However, upon receipt of realisation, the DEPB shall be endorsed transferable. In cases where the applicant applies for DEPB after realisation, the DEPB shall be issued with transferable endorsement”.

(9) The following shall be added at the end of paragraph 15.4 :

“Provided, however, the licensing authority issuing the IEC code may, for sufficient reasons to be recorded in writing, condone the delay on payment of a penalty of Rs. 5000/-”.

(10) The word ‘ownership’ appearing in the heading of paragraph 15.4 stands deleted.

(11) The following shall be added under Appendix 32B :

“TUV bayren (India), 312, Neelkhanth Commercial Centre, Sahar Road, Sahar, Mumbai-400099”

(12) The heading of the Appendix 32B shall be amended to read as ‘list of IS/ISO 9000 (series) Certification agencies’.

(13) List of WHOGMP Certification agencies.

(a) Drug Controllers/FDA Commissioners of the concerned states.

(14) The following shall be added in column 4 relating to value cap for calculation of DEPB entitlement against S. No. 65 of electronics products as given in Appendix 28A.—‘Rs. 750/- per piece’.

(15) the following shall be added as paragraph 6.8A :

“EPCG applications relating to Electronics and Software sector shall be considered by the regional licensing authorities concerned as per the financial power given below, on the basis of the recommendation received from the nodal/designated officer of Deptt. of Electronics with regard to the nexus of capital goods with export :

CIF VALUE	Competent Authority
Up to Rs. 2 Crore	The head of the regional licensing authority
Above Rs. 2 Crore and upto 10 Crore	Zonal Jt. DGFT
Above Rs. 10 Crore but upto Rs. 20 Crore	DGFT
Above Rs. 20 Crore	Commerce Secretary

A copy of the application shall be sent to the concerned nodal/designated officer of the Deptt. of Electronics and upon the receipt of the recommendation, the licenses shall be issued without putting the same to the EPCG Committee”.

(16) The following shall be added in column 4 after S. No. (v) against the jurisdiction of Jt. DGFT, CLA as given in S. No. 2 of column 2.

(vi) Saharanpur.

Consequently, the district Saharanpur mentioned in column 4 against S. No. 10 stands deleted and Mujaffarnagar is re-numbered as S. No. (i).

This issues in public interest.

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade